

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में  
सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 10644/2024

रामनाथ प्रसाद, पुत्र - वासुदेव प्रसाद , वार्ड No.11, मछरगावा, नौतन दुबे,  
जिला -पश्चिम चंपारण, बिहार- 845438

.....  
याचिकाकर्ता

बनाम

1. सी.जी.एस.टी. और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के प्रधान आयुक्त, केंद्रीय राजस्व भवन, (अनुलग्नक), बीर चंद पटेल पथ, पटना 800001
2. अतिरिक्त आयुक्त, सी.जी.एस.टी. और सी.एक्स., पटना-2, सी.टी.टी.सी. भवन, संचार परिसर, बुद्ध मार्ग, पटना-800001

..... उत्तरदाता

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता के लिए : श्री डी. वी. पाथी, वरिष्ठ अधिवक्ता  
श्री सदाशिव तिवारी, अधिवक्ता  
सुश्री प्राची पल्लवी, अधिवक्ता  
श्री हिरेश करण, अधिवक्ता  
श्री शिवानी देवाला, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए : श्री डॉ. कृष्ण नंदन सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता(ए. एस.  
जी.)  
श्री अंशुमन सिंह, सीनियर एससी, सी.  
जी.  
एस. टी. और सी.एक्स.  
श्री शिवादित्य धारी सिन्हा, अधिवक्ता  
श्री अमरजीत, अधिवक्ता

रिट याचिका -केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा जारी सेवा कर,  
ब्याज और दंड लगाने के आदेश को पूर्व-शो-काँज़ परामर्श (Pre-Show  
Cause Consultation) के बिना जारी करने के कारण रद्द करने हेतु

दायर की गई थी।

निर्णय -मांग-सह-शो-काँज़ नोटिस जारी होने से पहले ही याचिकाकर्ता को अपने समर्थन में दस्तावेज़ और जानकारी प्रस्तुत करने का अवसर मिला था, लेकिन उसने उस अवसर का लाभ नहीं उठाया। (पैराग्राफ 25)

याचिकाकर्ता को न्यायनिर्णयन प्रक्रिया (*adjudication proceeding*) के दौरान भी पर्याप्त अवसर दिया गया, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ऐसी स्थिति में, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के उल्लंघन के आधार पर विवादित आदेश को रद्द करने की कोई आवश्यकता नहीं है। - कुछ परिस्थितियों में पूर्व-शो-काँज़ परामर्श अनिवार्य हो सकता है, लेकिन संबंधित सर्कुलर के सीधे अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि यदि मामला धोखाधड़ी, मिलीभगत, जानबूझकर गलत विवरण, तथ्यों को छिपाने, कर चोरी आदि से संबंधित हो, तो पूर्व-शो-काँज़ नोटिस अनिवार्य नहीं है। (पैराग्राफ 26)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायालय, किसी मामले में धोखाधड़ी हुई है या नहीं, इसकी जांच करने से स्वयं को रोकने का सिद्धांत अपनाएगा। यह विचार अपील प्राधिकरण (*Appellate Authority*) द्वारा किया जाएगा। (पैराग्राफ 28)

जब याचिकाकर्ता स्वयं सहयोग नहीं कर रहा था और विभाग द्वारा जारी नोटिस का जवाब नहीं दे रहा था, तो विभाग के लिए 1994 अधिनियम की धारा 73(4B) के खंड (b) के तहत निर्धारित सीमा अवधि के भीतर सेवा कर की राशि निर्धारित करना संभव नहीं था। (पैराग्राफ 30)

आयकर विभाग से प्राप्त जानकारी और अन्य सामग्रियों को सक्षम प्राधिकारी ने सत्यापित करने की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान यदि याचिकाकर्ता सहयोग नहीं करता है और उपलब्ध सामग्री कर चोरी का संकेत देती है, तो प्राधिकरण के लिए यह मान लेना कि आसेसी (*Assessee*) कर चोरी के इरादे से सूचना प्रदान नहीं कर रहा है, गलत नहीं होगा। (पैराग्राफ 34)

यदि याचिकाकर्ता आज से आठ सप्ताह के भीतर एक विधिवत अपील दायर करता है, तो आयुक्त (अपील), CGST एवं CX सीमा-समय (Limitation) के मुद्दे पर विचार करेगा। (पैराग्राफ 40)

रिट याचिका का निपटारा किया जाता है। (पैराग्राफ 42)

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

समक्ष:- माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रंजन प्रसाद  
 और  
 माननीय न्यायमूर्ति रमेश चंद मालवीय  
 मौखिक निर्णय  
 (प्रति: माननीय न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद)

मौखिक निर्णय: 28-01-2025

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री सदाशिव तिवारी की सहायता से विद्वान वरिष्ठ वकील श्री डी. वी. पैथी और उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वरिष्ठ स्थायी वकील श्री अंशुमन सिंह की सहायता से विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल डॉ. के. एन. सिंह को सुना।

2. निम्नलिखित राहतों के लिए इस रिट आवेदन दायर की गई है:

(i) प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा 2015-2016 और 2016-17 की अवधि के लिए पारित दिनांक 02.01.2024 के आदेश (जैसा कि अनुलग्नक-पी2 में निहित है) में केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा जारी दिनांक 10.03.2017 के मास्टर परिपत्र संख्या 1053/02/2017-सीएक्स के अनुसार पूर्व कारण बताओ परामर्श के बिना सेवा कर, ब्याज और जुर्माना लगाने का प्रस्ताव किया गया था और बाद में दिनांक 19.11.2020 के परिपत्र द्वारा स्पष्ट किया गया था, को रद्द किया जाए।

(ii) प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा पारित दिनांक 02.01.2024 के आदेश

(जैसा कि अनुलग्नक-पी 2 में निहित है) जिसमें 2015-2016 और 2016-17 की अवधि के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी छूट अधिसूचना संख्या 25/2012-सेवा कर दिनांक 20.06.2012 पर विचार किए बिना सेवा कर, ब्याज और जुर्माना लगाया गया, जो सीमा की अवधि से परे पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बिना है, को दरकिनार और रद्द कर दिया जाए।

(iii) अन्य कोई राहत जिसके लिए याचिकाकर्ता भिन्न प्रकार से हकदार पाया जाए।

### मामले के संक्षिप्त तथ्य

3. याचिकाकर्ता माल परिवहन के व्यवसाय में लगा हुआ है, जिसने 05.02.2014 को बिहार राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (जिसे आगे "निगम" कहा जाएगा) के साथ एक जिले के भीतर या दूसरे जिले में तथा राज्य के बाहर से खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुओं के परिवहन के लिए एक समझौता किया था, जिसमें हैंडलिंग और अस्थायी भंडारण आदि शामिल हैं। प्रतिवादी नं. 1 द्वारा याचिकाकर्ता को कारण दर्शाओ नोटिस जारी किया गया है, यह कहते हुए कि वह कर योग्य सेवा प्रदान कर रहा है और उसने वित्तीय वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए कर योग्य कारोबार को दबा दिया है। हालाँकि, याचिकाकर्ता ने ऐसा कोई नोटिस प्राप्त होने से इनकार किया है और कहा है कि उसे केवल कारण बताओ नोटिस का अनुस्मारक प्राप्त हुआ है। उक्त कारण बताओ नोटिस का पालन नहीं किया गया है। प्रत्यर्थी नं- 1 ने एक एकतरफा आदेश

पारित किया जिसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65 (इसके बाद '1994 का अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के तहत बाद के संशोधनों के साथ कर योग्य सेवाएं प्रदान करने में लगा हुआ है और यह मेगा छूट अधिसूचना संख्या 25/2012-सेवा कर दिनांक 20.06.2012 की किसी भी प्रविष्टि के तहत नहीं आता है, जैसा कि संशोधित किया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 02.01.2024 के आदेश के अनुसार अनुलग्नक 'पी2' (जिसे आगे 'अक्षेपित आदेश' कहा जाएगा) में निहित माना कि याचिकाकर्ता ने 1994 के अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए कर योग्य टर्नओवर को छुपाया है और 1,26,03,035/- रुपये का सेवा कर और अन्य दंड और ब्याज के साथ एक समतुल्य जुर्माना लगाया है।

### याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुतियाँ

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील ने विभिन्न आधारों पर अक्षेपित आदेश का विरोध किया है। अक्षेपित आदेश का हवाला देते हुए, विद्वान वरिष्ठ वकील निवेदन करते हैं कि अक्षेपित आदेश अवलोकन से पता चलेगा कि तत्काल मामले में कार्यवाही की शुरुआत इस याचिकाकर्ता को दिनांक 28.04.2021 का मांग-सह-कारण-प्रदर्शन नोटिस जारी कर की गई थी। उनका कहना है कि मूल्यांकन प्राधिकारी ने वित्तीय वर्ष 2015-16 और 2016-17 के संबंध में अक्षेपित आदेश (अनुलग्नक 'पी2') पारित किया है। प्रत्येक निर्धारण वर्ष एक स्व-निहित मूल्यांकन वर्ष

होता है और अलग-अलग विवरणी दाखिल की जाती है, इसलिए, निर्धारण प्राधिकरण पर अलग-अलग कारण बताएँ नोटिस जारी करना अनिवार्य था।

5. विद्वान वरिष्ठ वकील निवेदन करते हैं कि 28.04.2021 पर जारी किया गया कारण बताएँ नोटिस 1994 के अधिनियम की धारा 73 की उप-धारा (1) के तहत निर्धारित सीमा की अवधि के बीच होगा। संबंधित अवधि के दौरान, नोटिस के लिए निर्धारित सीमा की अवधि केवल 18 महीने की थी, लेकिन इस मामले में, नोटिस संबंधित तिथि से क्रमशः पांच साल और चार साल बाद जारी किया गया था। इस प्रकार, यह निवेदन किया गया है कि कारण बताओ नोटिस जारी करना अधिनियम 1994 की धारा 73 की उप-धारा (1) द्वारा प्रभावित होगा।

6. उनकी एक दलील यह है कि कारण बताओ नोटिस जारी करने से पहले, मूल्यांकन अधिकारी का कर्तव्य था कि वह पूर्व-परामर्श नोटिस जारी करे। इस संबंध में, विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करते हैं कि यह एक अनिवार्य प्रावधान है जिसे सक्षम प्राधिकारी को प्रदत्त वैधानिक शक्तियों के आधार पर अस्तित्व में लाया गया है और इस संबंध में निर्देशों को प्रकृति में अनिवार्य माना गया है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस न्यायालय को परिपत्र संख्या 1053/02/2017 - सीएक्स दिनांक 10 मार्च, 2017 के पैराग्राफ '5.0' के माध्यम से अवगत कराया है, जिसके साथ मास्टर परिपत्र संलग्न है। मास्टर सर्कुलर के पैराग्राफ 5 के अनुसार, बोर्ड ने एफ. नं. 1080/09 डी. एल. ए./एम. आई. एस. सी./15 दिनांक 21 दिसंबर, 2015 से जारी निर्देश के अनुसार (निवारक/अपराध से संबंधित एस. सी.

एन. को छोड़कर) अनिवार्य रूप से 1 लाख से अधिक शुल्क की मांगों से जुड़े मामलों में कारण बताएँ नोटिस जारी करने से पहले प्रधान आयुक्त/आयुक्त द्वारा पूर्व-कारण बताएँ नोटिस परामर्श का प्रावधान किया है। इसमें कहा गया है कि इस तरह का परामर्श न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा संबंधित निर्धारिती के साथ किया जाएगा। अपने तर्कों को मजबूत करने के लिए, विद्वान वरिष्ठ वकील ने माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों पर क्रमशः भरोसा किया है-- रोचेम सेपरेशन सिस्टम्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य (रिट याचिका संख्या 822/2021 और एनालॉगस मामले दिनांक 30.01.2023); एमेडियस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम प्रधान आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और केंद्रीय कर आयुक्तालय 2019 एससीसी ऑनलाइन डेल 8437 और प्रधान आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और केंद्रीय कर आयुक्तालय बनाम एमेडियस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (विशेष अनुमति याचिका (सिविल) डायरी संख्या 35886/2019 दिनांक 04.11.2019) (अनुलग्नक 'पी5', 'पी6' और 'पी8' क्रमशः)। इस न्यायालय को अनुलग्नक 'पी/8' दिखाकर सूचित किया गया है कि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

7. विद्वान वरिष्ठ वकील ने 1994 के अधिनियम की धारा 73 की उप-धारा (4 बी) के माध्यम से इस न्यायालय को यह प्रस्तुत किया



है कि यह प्रावधान केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी के लिए उप-धारा (1) के प्रावधान के तहत आने वाले मामलों के संबंध में नोटिस की तारीख से एक वर्ष के भीतर उप-धारा (2) के तहत देय कर की राशि निर्धारित करना अनिवार्य बनाता है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने अपनी दलीलों पर बहुत जोर दिया है कि इस याचिकाकर्ता का मामला धारा 73 की उप-धारा (1) के प्रावधान या धारा 73 की उप-धारा (4) के तहत नहीं आएगा क्योंकि इसे (ए) से (ई) के किसी भी कारण के तहत आने वाले मामले में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। उनके अनुसार, इस मामले में अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है जो इस न्यायालय को संतुष्ट कर सके कि यह धोखाधड़ी या मिलीभगत या जानबूझकर गलत कथन या तथ्यों को दबाने या सेवा कर के भुगतान से बचने के इरादे से अध्याय 5 या उसके तहत बनाए गए नियमों के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन का मामला होगा।

8. यह उनका निवेदन है कि केवल उन मामलों में जो धारा 73 की उपधारा (1) के प्रावधान के तहत प्रदान की गई किसी भी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, उपधारा (1) का प्रावधान जो 18 महीने की सीमा निर्धारित करता है, उसे इस प्रकार पढ़ा जाएगा मानो 18 महीने के स्थान पर सीमा की अवधि पांच वर्ष होगी।

9. यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रतिवादी वर्तमान मामले में पांच साल की सीमा लागू नहीं कर सकते हैं। इस मामले को कर चोरी की श्रेणी में रखने के लिए प्रत्यर्थियों ने जिस एकमात्र दस्तावेज पर भरोसा

किया है, वह है आयकर की कार्यवाही में उपलब्ध जानकारी, फॉर्म 26 एएस जिसमें स्रोत पर काटे गए करों का विवरण होता है और जो इस याचिकाकर्ता के पैसों के खिलाफ स्रोत पर काटे गए कर की कुल राशि को दर्शाता है। किसी भी परिस्थिति में, इसे धोखाधड़ी या गलत कथन या कर चोरी का मामला नहीं कहा जा सकता है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने अपनी दलीलों को मजबूत करने के लिए परिपत्र निर्देश संख्या 05/2023-GST (पैराग्राफ '3.3') पर भरोसा किया है।

10. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि उप-धारा (4 बी) को इस प्रकार पढ़ा जा सकता है जैसे कि यह पूर्ण नहीं है, लेकिन उप-धारा (4 बी) के अंतर्गत खंड (ए) और (बी) के अंतर्गत आने वाले शब्दों "जहां ऐसा करना संभव है" का समूह मूल्यांकन प्राधिकारी पर इस न्यायालय को यह संतुष्ट करने का कर्तव्य डालता है कि वे काम पर थे, लेकिन उनके सभी प्रयासों के बावजूद कार्यवाही संभवतः दी गई सीमा अवधि के भीतर समाप्त नहीं हो सकी।

11. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस न्यायालय के समक्ष सीडब्ल्यूजेसी संख्या 18398/2023 (मेसर्स कनक ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ एवं अन्य) में दिनांक 04.04.2024 को इस न्यायालय की विद्वान समन्वय पीठ द्वारा पारित निर्णय के आदेश की एक प्रति प्रस्तुत की है, जिसमें प्रस्तुत किया गया है कि उक्त मामले में माननीय खंडपीठ ने यह विचार किया है कि वैधानिक प्रावधान के अनुसार प्राधिकारियों को ऐसा करने के लिए सभी संभव कदम

उठाने होंगे तथा एक वर्ष के भीतर कार्यवाही समाप्त करनी होगी। उक्त मामले में चूंकि न्यायालय इस बात से संतुष्ट था कि पूरे एक वर्ष की अवधि में कोई कदम नहीं उठाया गया, अतः विलम्ब के परिणामस्वरूप वैधानिक रूप से अपेक्षित शीघ्रता का लक्ष्य विफल हो जाएगा, इसलिए न्यायालय ने कार्यवाही जारी रखने की अनुमति नहीं दी।

12. विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सी.सी., सी.ई. और एस.टी. बेंगलोर (न्यायनिर्णय) एवं अन्य बनाम नॉर्दर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड (2022) 17 एससीसी 90 के मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा करते हुए कहा कि विस्तारित सीमा अवधि के आह्वान के सिद्धांतों पर विचार करते समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11-ए के संदर्भ में कॉस्मिक ड्राई केमिकल बनाम सी.सी.ई. (1995) 6 एससीसी 117 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहले व्यक्त किए गए नियमों का हवाला दिया है, जो कि 1994 के अधिनियम की धारा 73 के समान है। फैसले में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जहां तक धोखाधड़ी और मिलीभगत का संबंध है, आवश्यक घटक कर्तव्य से बचने का इरादा होगा और यह घटक इन शब्दों में अंतर्निहित है। कॉस्मिक ड्राई केमिकल (उपरोक्त) के मामले में फैसले के पैराग्राफ '6' को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया है। यह न्यायालय उचित स्तर पर इसे पुनः प्रस्तुत करेगा।

13. विद्वान वरिष्ठ वकील ने इस न्यायालय को समझौते (अनुलग्नक 'पी1') के माध्यम से अवगत कराया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि निगम और इस याचिकाकर्ता के बीच हुए समझौते के अवलोकन पर, यह प्रतीत होता है कि निगम को अनाज और चीनी, खाद्य तेल, कपड़े आदि सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं को सड़क मार्ग से जिले के भीतर या दूसरे जिले में और जिले के बाहर से परिवहन की व्यवस्था करने की आवश्यकता थी, जिसमें पूरे या आंशिक रूप से स्वामित्व वाले या किराए पर लिए गए गोदामों में उनका संचालन और/या अस्थायी भंडारण भी शामिल था। इस उद्देश्य के लिए, याचिकाकर्ता की सेवाएं ली गईं और एक समझौता किया गया।

14. विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करते हैं कि इस स्तर पर, यह न्यायालय रिट आवेदन के अनुलग्नक 'पी4' में निहित मेगा छूट अधिसूचना संख्या 25/2012 पर ध्यान दे सकता है। इस न्यायालय का ध्यान मद सं. 21 (क) की ओर आकर्षित किया गया है यह प्रदर्शित करने के लिए कि माल परिवहन एजेंसी द्वारा फल, सब्जियां, अंडे, दूध, खाद्यान्न या दालों के परिवहन के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं को सेवा कर के अधीन नहीं किया जाएगा। इसे कर योग्य सेवाओं की सूची से छूट दी गई है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि याचिकाकर्ता द्वारा प्रदान की गई सेवा मेगा छूट अधिसूचना (अनुलग्नक 'पी4') के आधार पर कर योग्य नहीं थी, तो याचिकाकर्ता को सेवा कर के लिए देय सेवा के कारण प्राप्त आय के रूप में उक्त समझौते के तहत ऐसी प्राप्तियों से प्राप्त

प्राप्तियों को दर्शाते हुए विवरणी दाखिल करने का कोई दायित्व नहीं था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि ऐसी परिस्थिति में, निर्धारण प्राधिकरण ने अक्षेपित आदेश पारित करने में गलती की है जिसके तहत और जिसके अंतर्गत 1,26,03,035/- रुपए की सेवा कर राशि की पुष्टि की गई है और याचिकाकर्ता को ब्याज और जुर्माने के साथ उक्त राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया है।

15. विद्वान वरिष्ठ वकील निवेदन करते हैं कि वास्तव में आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक 'पी2') के अवलोकन से, यह स्पष्ट होगा कि मूल्यांकन के साथ-साथ दंड की कार्यवाही एक साथ की गई है और उसी निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सेवा कर के साथ-साथ दंड की पुष्टि की गई है जो उचित नहीं होगा और कानून के विपरीत ठहराने योग्य है।

### प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुतियाँ

16. दूसरी ओर, श्री डॉ. के. एन. सिंह, विद्वान ए.एस.जी. ने रिट आवेदन को चुनौती दी है। यह प्रस्तुत किया गया है कि इस मामले का मूल आधार आयकर रिटर्न में निहित जानकारी है, जो दर्शाती है कि इस मामले में धारा 194 (सी) के तहत याचिकाकर्ता से स्रोत पर कर काटा गया है, जो एक अनुबंध के तहत काम कर रहा था और उसने उक्त अनुबंध कार्य के लिए निगम से बड़ी राशि प्राप्त की थी। विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करते हैं कि कानून उत्तरदाताओं को तीसरे पक्ष की जानकारी को ध्यान में रखने से नहीं रोकता है, इसलिए इस तथ्य में कोई अवैधता नहीं

पाई जा सकती है कि तत्काल कार्यवाही आयकर कार्यवाही में उपलब्ध जानकारी के आधार पर शुरू की गई है, विशेष रूप से, फॉर्म 26 एस में।

17. विद्वान वरिष्ठ वकील ने इस न्यायालय को जवाबी हलफनामे के पैराग्राफ '10' के माध्यम से अवगत कराया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि नोटिस प्राप्तकर्ता को अपना जवाब प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया था, लेकिन 28.04.2021 पर जारी कारण बताओ नोटिस की जानकारी होने के बावजूद, नोटिस प्राप्तकर्ता ने कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। यह बताया गया है कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देते हुए कई तिथियां तय कीं। चार बार नोटिस पाने वाले को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित होने का अवसर दिया गया था। नोटिस प्राप्तकर्ता 30.10.2023 पर उपस्थित हुआ और चार सप्ताह के समय के लिए अनुरोध करते हुए एक पत्र प्रस्तुत किया। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने अनुरोध पर विचार किया और बचाव पक्ष के निवेदन की प्रतीक्षा की लेकिन याचिकाकर्ता अपना जवाब प्रस्तुत करने में विफल रहा। अंततः, वर्तमान रिट आवेदन में आरोपित मूल आदेश 02.01.2024 को जारी किया गया था।

18. विद्वान वरिष्ठ वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि यदि नोटिस प्राप्तकर्ता को मूल रूप से उक्त आदेश के साथ कोई शिकायत है, तो उनके पास आदेश प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनों की अवधि के भीतर आयुक्त (अपील) सी.जी.एस.टी. और सी.एक्स., पटना के समक्ष अपील के

माध्यम से एक उपाय है, लेकिन इस मामले में, याचिकाकर्ता ने अपील करने के अपने अधिकार का आह्वान करने के बजाय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय से संपर्क करने का विकल्प चुना है। निवेदन यह है कि जहां याचिकाकर्ता के लिए एक समान रूप से प्रभावी उपाय उपलब्ध है, एक रिट कोर्ट आत्म-संयम का प्रयोग कर सकता है और एक रिट आवेदन पर विचार नहीं कर सकता है।

19. विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता की ओर से अनुरोध किए गए सीमा का मुद्दा 1994 के अधिनियम की धारा 73 के तहत निहित प्रावधानों के बावजूद याचिकाकर्ता के लिए उपलब्ध नहीं होगा। विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करते हैं कि वर्तमान मामले में, इस मामले को कर चोरी की श्रेणी में रखते हुए कार्यवाही शुरू की गई थी। इस न्यायालय का ध्यान अक्षेपित आदेश में उल्लिखित मामले के संक्षिप्त तथ्यों की ओर आकर्षित किया गया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि मूल्यांकन प्राधिकारी ने धारा 73 की उप-धारा (1) के प्रावधान के तहत (ए) से (ई) के तहत बताए गए कारणों में से एक के लिए इस मामले को उठाया है। इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया गया है कि मामला पांच साल की सीमा की विस्तारित अवधि के अंतर्गत आएगा।

20. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधिनियम 1994 की धारा 73 की उपधारा (4 बी) में दो खंड दिए गए हैं और दोनों खंडों के अंतर्गत सीमा अवधि निश्चित की गई है, लेकिन उन प्रावधानों को पढ़ने से पता चलता है कि वे अनिवार्य प्रकृति के नहीं हैं। यह

प्रस्तुत किया गया है कि मेसर्स कनक ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में, इस न्यायालय की विद्वान समन्वय पीठ ने, यद्यपि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने विवेक का प्रयोग किया और कार्यवाही जारी रखने की अनुमति नहीं दी, लेकिन साथ ही, अपने फैसले के पैराग्राफ '10' में, माननीय खंडपीठ ने इस दलील के साथ अपनी सहमति व्यक्त की कि यह पूर्ण अधिदेश नहीं है कि कार्यवाही नोटिस से एक वर्ष के भीतर पूरी हो जानी चाहिए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अभिलेख पर यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि एक वर्ष की इस अवधि के दौरान, निर्धारण प्राधिकरण के ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई थी और सीमा की अवधि के भीतर कार्यवाही को समाप्त करना संभव था। यह बताया गया है कि कारण बताओ नोटिस कोविड-19 अवधि के दौरान जारी किया गया था और इस न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान रिट याचिका (सिविल) संख्या 03/2020 के मामले में दिए गए निर्णय के अनुसार कोविड-19 अवधि का लाभ विभाग को भी समान रूप से मिलेगा। कोविड के बाद, याचिकाकर्ता को निर्णय की कार्यवाही में भाग लेने के कई अवसर दिए गए थे। इस तथ्य से कोई इनकार नहीं है कि याचिकाकर्ता को कई बार स्थगन दिया गया था, वह वास्तव में पेश हुए और स्थगन की मांग की लेकिन उसके बाद कार्यवाही को छोड़ दिया। ऐसी परिस्थिति में, जहां विभाग ने स्थगन के लिए उनके अनुरोध को स्वीकार करने के बाद उनके जवाब का इंतजार किया है, याचिकाकर्ता को यह कहने का अधिकार नहीं होगा कि मूल आदेश (अनुलग्नक 'पी2') पर सीमा कानून का प्रभाव पड़ेगा।



21. यह प्रस्तुत किया जाता है कि जहां तक समझौते (अनुलग्नक 'पी1') के तहत याचिकाकर्ता द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए सेवा कर की प्रभार्यता का संबंध है, यह एक विशुद्ध तथ्य का प्रश्न होगा जिस पर अपीलीय प्राधिकरण द्वारा विचार करने की आवश्यकता होगी और चूंकि अपील मूल कार्यवाही की निरंतरता होगी, इसलिए याचिकाकर्ता को अपील के उपचार के लिए पुनः नियुक्त करना हमेशा उचित होगा। धारा 73 की उप-धारा (2ए) का उल्लेख किया गया है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस न्यायालय के समक्ष **सीडब्ल्यूजेसी संख्या 4541/2024 (मेसर्स मंगल मूर्ति कंस्ट्रक्शन बनाम भारत संघ एवं अन्य)** में इस न्यायालय की एक अन्य विद्वान समन्वय पीठ के निर्णय की एक प्रति प्रस्तुत की है, जिसमें प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान समन्वय पीठ ने उक्त मामले में एक समान प्रस्तुतिकरण को देखते हुए यह विचार किया है कि याचिकाकर्ता प्रासंगिक प्रावधान के तहत सेवा कर से छूट का हकदार होगा या नहीं, इसकी जांच अपेक्षित दस्तावेजों और महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में की जानी चाहिए। इसलिए विद्वान समन्वय पीठ ने **गोदरेज सारा ली लिमिटेड बनाम आबकारी एवं कराधान अधिकारी-सह-मूल्यांकन प्राधिकरण एवं अन्य (2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 95)** (पैरा '4') और **शालिनी श्याम शेटी एवं अन्य बनाम राजेंद्र शंकर पाटिल (2010) 8 एससीसी 329** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए यह विचार किया कि यह न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए रिट

आवेदन में शामिल मुद्दे पर निर्णय नहीं ले सकता। उक्त मामले में याचिकाकर्ता को अपील में अपना उपाय तलाशने के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण में भेज दिया गया था। यह उनका निवेदन है कि वर्तमान अपील में भी इसी तरह का विचार लिया जाए।

22. विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे कहा है कि चूंकि इस मामले को याचिकाकर्ता द्वारा कर चोरी की श्रेणी में रखा गया है, इसलिए याचिकाकर्ता पर यह दायित्व होगा कि वह ठोस सामग्री प्रस्तुत करके और न्यायिक घोषणाओं के बल पर यह प्रदर्शित करने के लिए कि यह कर चोरी की श्रेणी में नहीं आएगा, अपीलीय प्राधिकरण को संतुष्ट करे। याचिकाकर्ता के इरादे पर अपीलीय प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाना अपेक्षित है, इसलिए यह न्यायालय मामले के इस पहलू पर अपने विचार दर्ज नहीं कर सकता, क्योंकि यह अच्छी तरह से स्थापित है कि धोखाधड़ी के मुद्दे में अनिवार्य रूप से तथ्य का प्रश्न शामिल होगा।

23. यह भी बताया गया है कि जहां तकसर्स कनक ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में फैसले का सवाल है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया है, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि अक्षेपित फैसले में कानून का कोई सिद्धांत नहीं दिया गया है। इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय की विवेकाधीन और पूर्ण शक्ति के प्रयोग के लिए मामला नहीं बनाया है।

## विचार

24. हमने दोनों पक्षों के विद्वान वरिष्ठ वकील को विस्तार से सुना है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया है। सबसे पहले, हम इस तथ्य पर ध्यान देते हैं कि भले ही जवाबी हलफनामे की एक प्रति याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को 21.08.2024 पर वापस दी गई थी, लेकिन याचिकाकर्ता ने जवाबी हलफनामे में तथ्यों के बयान का खंडन नहीं किया है। जवाबी हलफनामे के पैराग्राफ '10 में, उत्तरदाताओं ने याचिकाकर्ता को दिनांकित 28.04.2021 के कारण बताए जाने के नोटिस का जवाब देने के लिए दिए गए अवसरों का विवरण दिया है। यह कहा गया है कि दिनांक 28.04.2021 को मांग-सह-कारण बताओ नोटिस जारी करने से पहले, आयकर विभाग द्वारा प्रदान की गई तिथि के सत्यापन/समाधान के लिए दस्तावेज/सूचना प्रस्तुत करने के लिए विभाग द्वारा दिनांक 13.04.2021 के पत्र, दिनांक 14.04.2021 के ईमेल और दिनांक 20.04.2021 के अनुस्मारक के माध्यम से नोटिस प्राप्तकर्ता को तीन अवसर दिए गए थे, लेकिन नोटिस प्राप्तकर्ता ने कोई जवाब नहीं दिया। यह आगे कहा गया है कि मांग-सह-कारण-प्रदर्शन नोटिस जारी करने से पहले पर्याप्त अवसर देने के बावजूद, जब नोटिसकर्ता ने जवाब नहीं दिया तो 28.04.2021 पर मांग-सह-कारण-प्रदर्शन नोटिस जारी किया गया था, जिसमें नोटिसकर्ता को अपना बचाव जवाब जमा करने के लिए 30 दिनों का समय दिया गया था। नोटिसकर्ता ने मांग-सह-कारण-प्रदर्शन नोटिस के खिलाफ कोई बचाव जवाब प्रस्तुत नहीं किया और न ही वह न्यायनिर्णायक

प्राधिकरण के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई के लिए निर्धारित तारीखों में से किसी पर आया। चार बार नोटिस पाने वाले को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होने का अवसर दिया गया था, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुआ। इसके बाद, नोटिस प्राप्तकर्ता ने अपने दिनांकित 30.10.2023 पत्र के माध्यम से न्यायनिर्णायक प्राधिकरण से चार सप्ताह का समय देने का अनुरोध किया। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने इस अनुरोध पर विचार किया और बचाव पक्ष के निवेदन की प्रतीक्षा की लेकिन याचिकाकर्ता अपना बचाव दाखिल करने में विफल रहा।

25. चूंकि जवाबी हलफनामे के पैराग्राफ '10' में निहित ये बयान निर्विवाद रहे, इसलिए हमें यह विचार रखने में कोई कठिनाई नहीं है कि मांग-सह-कारण-प्रदर्शन नोटिस जारी करने से पहले भी याचिकाकर्ता के पास अपने समर्थन में सभी दस्तावेजों और सूचनाओं के साथ अपना जवाब प्रस्तुत करने का अवसर था, लेकिन उसने उस अवसर का लाभ नहीं उठाया।

26. न्यायनिर्णयन प्रक्रिया के दौरान भी उन्हें पर्याप्त अवसर दिया गया था, लेकिन उन्होंने इस अवसर का लाभ नहीं उठाया। ऐसी परिस्थिति में, अक्षेपित आदेश में *ऑडी अल्टरम पार्टम* (दूसरे पक्ष को भी सुनो) के सिद्धांत के उल्लंघन के आधार पर किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी। जहां तक विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के द्वारा उठाए गए कारण बताओ नोटिस से पूर्व परामर्श का मुद्दा है, इस कथन को स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं है कि कुछ परिस्थितियों में कारण बताओ नोटिस से पूर्व परामर्श अनिवार्य होगा, लेकिन संदर्भित परिपत्र को

पढ़ने से पता चलता है कि धोखाधड़ी, मिलीभगत, जानबूझकर गलत बयानबाजी, तथ्यों को छिपाना, कर चोरी आदि के तहत दर्ज मामलों में परामर्श से पूर्व नोटिस अनिवार्य नहीं है।

27. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील का तर्क कि 'धोखाधड़ी या मिलीभगत' को याचिकाकर्ता के इरादे के संदर्भ में स्थापित किया जाना चाहिए, न्यायिक घोषणा पर आधारित है और इस संबंध में, नॉर्दर्न ऑपरेटिंग सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय इस क्षेत्र को नियंत्रित करेगा। नॉर्दर्न ऑपरेटिंग सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में फैसले के पैराग्राफ '69' में जो कहा गया है, उसे तत्काल संदर्भ के लिए नीचे उद्धृत किया जा रहा है:-

69. राजस्व का यह तर्क कि निर्धारिती जानबूझकर दमन में लिप्त था, इस न्यायालय के सुविचारित दृष्टिकोण में, असंगत है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11-ए के संदर्भ में, जो वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 73 के समान है, कॉस्मिक ड्राई केमिकल बनाम सीसीई में पिछले तीन-न्यायाधीशों के फैसले का दृष्टिकोण यह था कि:  
(SCC pg. 119, Para 6)

“6. अब जहाँ तक धोखाधड़ी और मिलीभगत का संबंध है, यह स्पष्ट है कि अपेक्षित इरादा

यानी कर्तव्य से बचने का इरादा इन्हीं शब्दों में निर्मित है। जहाँ तक तथ्यों के गलत कथन या दमन का संबंध है, वे स्पष्ट रूप से "जानबूझकर" शब्द से योग्य हैं जो "गलत कथन या तथ्यों का दमन" शब्दों से पहले है जिसका अर्थ है कर्तव्य से बचने के इरादे से।' इस अधिनियम या नियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन' शब्दों के अगले समूह को फिर से 'शुल्क के भुगतान से बचने के इरादे से' तुरंत निम्नलिखित शब्दों द्वारा योग्य माना जाता है। इसलिए, यह कहना सही नहीं है कि तथ्य का दमन या गलत कथन हो सकता है, जो जानबूझकर नहीं है और फिर भी धारा 11-ए के परंतुक के उद्देश्य के लिए एक अनुमेय आधार है। तथ्य का गलत कथन या दमन जानबूझकर किया जाना चाहिए।“

28. उपरोक्त मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को पढ़ने पर, ऐसा प्रतीत होता है कि 'धोखाधड़ी' और 'मिलीभगत' को साबित करने के लिए कर्तव्य से बचने का इरादा होना आवश्यक है । इस आशय को कैसे एकत्र किया जाए या इसका न्याय कैसे किया जाए, यह

तथ्य का प्रश्न बना रहेगा और यह मुद्दा कि क्या यह धोखाधड़ी का मामला है, या जानबूझकर गलत कथन, मिलीभगत का मामला है या धारा 73 की उप-धारा (1) के परंतुक के किसी खंड (ए) से (बी) के तहत आता है, या तो न्यायनिर्णायक प्राधिकरण या अभिलेख पर सामग्री के संदर्भ में अपीलीय प्राधिकरण द्वारा उचित रूप से निर्णय लिया जा सकता है। यह न्यायालय अपीलीय प्राधिकरण की शक्तियों को हड़प नहीं लेगा। हमारी सुविचारित राय में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत बैठक करने वाला यह न्यायालय इस बात की जांच करने में आत्मसंयम के मामले के रूप में खुद को अलग रखेगा कि क्या यह धोखाधड़ी का मामला है या नहीं। इसे अपीलीय प्राधिकरण द्वारा विचार करने के लिए खुला छोड़ दिया गया है।

**29.** इस न्यायालय के समक्ष जो सीमाएं उठाई गई हैं, उनका जवाब प्रासंगिक प्रावधान पर ध्यान देने के बाद ही दिया जा सकता है। हम 1994 के अधिनियम की धारा 73 की धारा 73 (1) और (2) और उप-धारा (2ए) और (4बी) को पुनः प्रस्तुत करते हैं जो इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए रखे गए दो प्रासंगिक प्रावधान हैं:

**“धारा 73. न लगाया गया सेवा कर वसूलना या भुगतान किया गया या कम लगाया गया या कम भुगतान किया गया या गलती से वापस किया गया।**

(1) जहां कोई सेवा कर नहीं लगाया गया है या भुगतान नहीं किया गया है या कम कर दिया गया है या कम भुगतान किया गया है या गलत तरीके से

वापस किया गया है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी, संबंधित तिथि से तीस महीने के भीतर, सेवा कर के साथ प्रभार्य व्यक्ति को नोटिस दे सकता है जो नहीं लगाया गया है या भुगतान किया गया है या जो कम कर दिया गया है या कम भुगतान किया गया है या जिस व्यक्ति को ऐसा कर रिफंड गलती से किया गया है, जिससे उसे कारण दिखाने की आवश्यकता होती है कि उसे नोटिस में निर्दिष्ट राशि का भुगतान क्यों नहीं करना चाहिए:

बशर्ते कि जहां निम्नलिखित कारणों की वजह से यदि कोई सेवा कर नहीं लगाया गया है या भुगतान नहीं किया गया है या कम अवधि के लिए लिया गया है या कम अवधि के लिए भुगतान किया गया है या गलती से वापस किया गया है -

(क) धोखाधड़ी; या

(ख) संलिप्तता; या

(ग) जानबूझकर गलत कथन; या

घ) तथ्यों का दमन; या

(ड) सेवा कर से प्रभार्य व्यक्ति या उसके अभिकर्ता द्वारा सेवा कर के भुगतान से बचने के इरादे से इस अध्याय या उसके तहत बनाए गए नियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन, इस उप-धारा के प्रावधानों का प्रभाव होगा, जैसे कि, तीस महीने शब्दों के लिए, "पाँच वर्ष" शब्द प्रतिस्थापित किए गए थे।

(2) केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी, उस व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हो, जिस पर उप-धारा (1) के तहत नोटिस दिया गया है, पर विचार करने के बाद, ऐसे व्यक्ति (नोटिस में निर्दिष्ट राशि से अधिक नहीं होने पर) से देय या गलती से वापस की गई सेवा कर की राशि निर्धारित करेगा और उस पर ऐसा व्यक्ति इस तरह से निर्धारित राशि का भुगतान



करेगा।

(2 क) जहां कोई अपीलीय प्राधिकरण या न्यायाधिकरण या न्यायालय यह निष्कर्ष निकालता है कि उप-धारा (1) के परन्तुक के तहत जारी की गई सूचना इस कारण से टिकाऊ नहीं है कि-

(क) धोखाधड़ी; या

(ख) संलिप्तता; या

(ग) जानबूझकर गलत कथन; या

(घ) तथ्यों का दमन; या

(ङ) सेवा कर के भुगतान से बचने के इरादे से इस अध्याय या उसके तहत बनाए गए नियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन, सेवा कर से प्रभार्य व्यक्ति के खिलाफ स्थापित नहीं किया गया है, जिसे नोटिस जारी किया गया था, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी ऐसे व्यक्ति द्वारा तीस महीने की अवधि के लिए देय सेवा कर का निर्धारण करेगा, जैसे कि नोटिस उन अपराधों के लिए जारी किया गया था जिनके लिए उप-धारा (1) के तहत तीस महीने की सीमा लागू होती है।

(4 बी) केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी उप-धारा (2)-(ए) के तहत देय सेवा कर की राशि का निर्धारण नोटिस की तारीख से छह महीने के भीतर करेगा, जहां उप-धारा (1) के तहत आने वाले मामलों के संबंध में ऐसा करना संभव है; (बी) नोटिस की तारीख से एक साल के भीतर, जहां ऐसा करना संभव है, उप-धारा (1) के परन्तुक या उप-धारा (4 ए) के परन्तुक के तहत आने वाले मामलों के संबंध में।”

30. धारा 73 की उप-धारा (1) के खाली पढ़ने पर हम पाते

हैं कि इस प्रावधान के तहत नोटिस देने की सीमा की अवधि प्रासंगिक

समय पर 18 महीने थी, लेकिन उप-धारा (1) का परंतुक एक अपवाद बनाता है और यह स्पष्ट रूप से प्रदान करता है कि परंतुक के खंड (ए) से (ई) के तहत बताए गए कारणों में से किसी एक के तहत आने वाले मामलों में, उप-धारा के प्रावधान प्रभावी होंगे, जैसे कि "18 महीने" शब्दों के लिए, "पांच साल" शब्द प्रतिस्थापित किए गए हैं। चूंकि इस मामले को कर चोरी के रूप में लेते हुए कार्यवाही की शुरुआत की गई है, इसलिए उत्तरदाताओं ने सही तर्क दिया है कि इस मामले में सीमा की अवधि पाँच साल का होगा। हालाँकि, हम यह जोड़ने में जल्दबाजी करेंगे कि हम कोई भी निष्कर्ष दर्ज नहीं कर रहे हैं कि यह सेवा कर के भुगतान की चोरी का मामला है क्योंकि इस न्यायालय की ऐसी कोई भी राय याचिकाकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद न्यायसंगत और उचित निष्कर्ष पर पहुंचने में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण या अपीलीय प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण होगी। तथ्य यह है कि इस मामले को कर चोरी के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी, इसलिए, सीमा की अवधि पांच साल होगी। साथ ही, 1994 के अधिनियम की धारा 73 की उप-धारा (4 बी) को देखने के बाद, हमारी राय है कि इस उप-धारा को सीमा की पूर्ण अवधि प्रदान करने के रूप में नहीं लिया जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि विधायी इरादा यह है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त उप-धारा (2) के तहत देय सेवा कर की राशि का निर्धारण करेगा---(ए) उप-धारा (1) के तहत आने वाले मामलों के संबंध में, जहां नोटिस जारी करने की तारीख से छह महीने के भीतर ऐसा करना संभव है; (बी) नोटिस की तारीख से एक साल के

भीतर जहां उप-धारा (1) के परंतुक के तहत आने वाले मामलों के संबंध में ऐसा करना संभव है, शब्दों का समूह "जहां ऐसा करना संभव है" स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि विधानमंडलों का कभी भी यह विचार नहीं था कि जो कार्यवाही किसी भी कारण से सीमा अवधि के भीतर समाप्त नहीं होगी, वह केवल सीमा अवधि की समाप्ति के आधार पर बंद हो जाएगी। हमारे लिए, ऐसा प्रतीत होता है कि इस बारे में अदालत की राय कि क्या निर्धारित अवधि के साथ ऐसा करना संभव था, मामले-दर-मामले अलग होगी। इस मामले में, हमारी राय में, प्रत्यर्थियों ने इस न्यायालय को यह रिकॉर्ड देकर संतुष्ट किया है कि याचिकाकर्ता को भाग लेने का पर्याप्त अवसर प्रदान करने के लिए कई मौकों पर कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी और मांग-सह-कारण-प्रदर्शन नोटिस जारी करने से पहले भी, याचिकाकर्ता को कम से कम तीन मौकों पर अवसर दिया गया था। प्रत्यर्थियों के बयान निर्विवाद रहने के कारण, हमारा विचार है कि जहां याचिकाकर्ता स्वयं सहयोग नहीं कर रहा था और विभाग द्वारा जारी किए गए नोटिस का जवाब नहीं दे रहा था, तो विभाग के लिए 1994 के अधिनियम की धारा 73 की उप-धारा (4 बी) के खंड (बी) के तहत निर्धारित सीमा अवधि के भीतर सेवा कर की राशि निर्धारित करना संभव नहीं होता।

31. यह हमें याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील की अंतिम प्रस्तुति पर जाएगा जिसमें उन्होंने तर्क दिया है कि समझौते (अनुलग्नक 'पी1') के तहत प्रदान की जा रही सेवा की प्रकृति के आधार पर, याचिकाकर्ता द्वारा इस तरह प्रदान की गई सेवा सेवा कर के लिए

उत्तरदायी नहीं होगी। इस उद्देश्य के लिए, उन्होंने मेगा छूट अधिसूचना (अनुलग्नक 'पी4') पर भरोसा किया है। निर्देश संख्या 05/2023-जीएसटी दिनांक 13.12.2023 का पैराग्राफ '3.3' इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह प्रस्तुत किया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, मुंबई बनाम मेसर्स फिएट इंडिया (पी) लिमिटेड के मामले में सिविल अपील संख्या 1648-49/2004 में दिए गए निर्णय के पश्चात, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार यह निर्देश लेकर आई है। याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा हमसे अनुरोध किया गया है कि पैराग्राफ '3.1' से '3.3' में निहित इस निर्देश पर विचार किया जाए। हम तैयार संदर्भ के लिए इन अनुच्छेदों को यहाँ पुनः प्रस्तुत करेंगे:

“3.1 उद्योग द्वारा यह भी दर्शाया गया है कि कई मामलों में, क्षेत्र संरचनाएं यांत्रिक रूप से सी.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 74 (1) के तहत सीमा की विस्तारित अवधि का आह्वान कर रही हैं।

3.2 इस संबंध में सी.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 74 (1) इस प्रकार है:

“(1) जहां उचित अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि किसी भी कर का भुगतान नहीं किया गया है या कम भुगतान किया गया है या गलती से वापस किया गया है या जहां इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत तरीके से लाभ उठाया गया है या धोखाधड़ी के कारण उपयोग किया गया है, या कर से बचने के लिए जानबूझकर गलत बयान दिया गया है या तथ्यों को दबाया गया है।”

3.3 सी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 74 (1) के शब्दों

के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि धारा 74 (1) को केवल उन मामलों में लागू किया जा सकता है जहां उक्त करदाता की ओर से कर से बचने के लिए धोखाधड़ी या जानबूझकर गलत बयान या तथ्यों को दबाया जाता है। धारा 74 (1) को केवल जी. एस. टी. का भुगतान न करने के कारण, धोखाधड़ी या जानबूझकर गलत कथन या कर से बचने के लिए तथ्यों को दबाने के विशिष्ट तत्व के बिना लागू नहीं किया जा सकता है। इसलिए, केवल उन मामलों में जहां जांच से पता चलता है कि करदाता की ओर से धोखाधड़ी या जानबूझकर गलत बयान देने या कर चोरी करने के लिए तथ्यों को दबाने का ठोस सबूत है, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 74 (1) के प्रावधानों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए लागू किया जा सकता है, और ऐसे सबूतों को भी कारण बताओ नोटिस का हिस्सा बनाया जाना चाहिए”

**32.** निर्देशों को देखने पर, हम पाते हैं कि पैराग्राफ '3.3' में

जो कुछ भी कहा गया है, वह यह है कि सी.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 74 (1) को केवल जी.एस.टी. का भुगतान न करने के कारण, धोखाधड़ी या जानबूझकर गलत कथन या कर से बचने के लिए तथ्यों को दबाने के विशिष्ट तत्व के बिना लागू नहीं किया जा सकता है। इसमें आगे यह प्रावधान किया गया है कि केवल उन मामलों में जहां जांच से संकेत मिलता है कि करदाता की ओर से कर से बचने के लिए धोखाधड़ी या जानबूझकर गलत कथन या तथ्य को दबाने का ठोस सबूत है, सी.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 74 (1) के प्रावधानों को कारण बताएँ नोटिस जारी करने के लिए लागू किया जा सकता है और ऐसे साक्ष्य को भी कारण बताएँ नोटिस का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।

**33.** जहां तक वर्तमान मामले के तथ्यों का संबंध है, हम

आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक 'पी2') को पढ़ने पर पाते हैं कि निर्धारण अधिकारी ने पैराग्राफ '2' में दर्ज किया है कि आयकर विभाग द्वारा साझा किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि नोटिस प्राप्तकर्ता एक सेवा प्रदाता है और उसने 2015-16 और 2016-17 की अवधि के दौरान केवल 8,57,65,000/- रुपए प्राप्त किए हैं। आयकर विभाग से सेवा कर देनदारियों के संबंध में प्राप्त आंकड़ों को सत्यापित करने और उसके उचित निर्वहन के लिए, इस उचित विश्वास के तहत कि नोटिस प्राप्तकर्ता सेवा कर की चोरी कर रहा था, नोटिस प्राप्तकर्ता को सी.सं. IV(II)-थर्ड पार्टी/बीटीएच/2020/27 दिनांक 13.04.2021 और ईमेल दिनांक 14.04.2021 के माध्यम से पत्र भेजे गए, जिसके बाद अधीक्षक, सीजीएसटी और सीईएक्स रेंज, बेटिया द्वारा आयकर विभाग द्वारा प्रदान की गई तिथि के सत्यापन/समाधान के लिए कुछ दस्तावेज/रिकॉर्ड और जानकारी प्रस्तुत करने के लिए एक अनुस्मारक ईमेल दिनांक 20.04.2021 भेजा गया। अक्षेपित आदेश में इस तथ्य पर भी ध्यान दिया गया है कि नोटिस प्राप्तकर्ता की ओर से कोई जानकारी/प्रतिक्रिया नहीं दी गई है और इस वजह से, सक्षम प्राधिकारी ने एक राय बनाई है कि नोटिस प्राप्तकर्ता ने देय सेवा कर के भुगतान से बचने के एकमात्र इरादे से ऐसा किया है, इसलिए, विभाग आयकर विभाग द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को वैध मानते हुए उन्हें उचित मानने के लिए मजबूर था और सेवा कर और उपकर की गणना के लिए आगे बढ़ा।

**34.** हमारी सुविचारित राय में, निर्देश के खंड '3.3' को मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पढ़ा जाना चाहिए। इस मामले के

तथ्यों से पता चलेगा कि सक्षम प्राधिकारी को आयकर विभाग से जानकारी मिली है और सामग्री उन सामग्रियों को सत्यापित करने के लिए आगे बढ़ी है, लेकिन उक्त सत्यापन के दौरान, यदि याचिकाकर्ता सहयोग नहीं कर रहा था और सामग्री ने संकेत दिया कि यह कर की चोरी का मामला है, तो प्राधिकरण को यह उचित विश्वास होना गलत नहीं होगा कि निर्धारित कर से बचने के एकमात्र इरादे से नोटिस के जवाब में जानकारी प्रदान नहीं कर रहा है।

**35.** हमारी राय में, याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिक्रिया के अभाव में एक उचित विश्वास बनाने में सक्षम प्राधिकारी की ओर से कोई गलती नहीं पाई जा सकती है।

**36.** उपरोक्त चर्चाओं का परिणामतः न्यायालय यह निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित होता है कि इस न्यायालय के रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर में मूल अक्षेपित आदेश (अनुलग्नक 'पी2') में हस्तक्षेप करने का उपयुक्त मामला नहीं बनता है।

**37.** मेसर्स मंगल मूर्ति कंस्ट्रक्शंस (उपरोक्त) के मामले में, विद्वत समन्वय पीठ ने हाल ही में इसी तरह की परिस्थिति में दिए 18.01.25 के फैसले में याचिकाकर्ता को अपील के वैकल्पिक उपाय प्रदान करने के साथ देरी को माफ करने के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण से अनुरोध किया गया है।

**38.** याचिकाकर्ता, यदि ऐसा सलाह दी जाती है, तो आयुक्त, (अपील), सी.जी.एस.टी. और सी.एक्स. के समक्ष अपील के वैधानिक उपाय

का लाभ उठा सकता है।

**39.** श्री डी. वी. पैथी, विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करते हैं कि मूल अक्षेपित आदेश (अनुलग्नक 'पी2') दिनांक 02.01.2024 का है, इसलिए, अपील दायर करने की सीमा की अवधि समाप्त हो गई है। इस स्तर पर, विद्वान एएसजी ने प्रस्तुत किया कि यद्यपि सीमा अवधि समाप्त हो गई है, लेकिन इस न्यायालय द्वारा समय-समय पर कई मामलों में पारित निर्णय और आदेश के संदर्भ में, अपीलीय प्राधिकारी, पर्याप्त न्याय करने के लिए, उच्च न्यायालय में रिट आवेदन के लंबित रहने के कारण अपील पर विचार करें ।

**40.** उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों और हमारे समक्ष रखी गई सामग्रियों को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि यदि याचिकाकर्ता आज से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर विधिवत गठित अपील दायर करता है, तो अपीलीय प्राधिकरण यानी आयुक्त (अपील), सी.जी.एस.टी. और सी.एक्स. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए समय सीमा के मुद्दे पर विचार करेंगे कि याचिकाकर्ता को कानूनी रूप से इस न्यायालय से संपर्क करने की सलाह दी गई थी और रिट आवेदन इस न्यायालय में आक्षेपित निर्णय पर रोक लगाने के अंतरिम आदेश के साथ विचाराधीन था ।

**41.** यह उम्मीद की जाती है कि यदि समय सीमा की दलील दी जाती है तो अपीलीय प्राधिकरण इस बात को ध्यान में रखते हुए विचार करेगा कि पर्याप्त न्याय हमेशा बेहतर होता है।



42. इस रिट आवेदन का तदनुसार निष्पादन किया जाता है।

(राजीव रंजन प्रसाद, न्यायमूर्ति)

(रमेश चंद मालवीय, न्यायमूर्ति)

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।